(ख) क्या प्रत्येक मामले में इस आशय की जांच कर ली गई थी कि वे आवंटी अपने पूर्ववर्ती आवासों में नियमित रूप से रह रहे थे ; और

(ग) सरकारी आवास के मामले में नियमित रूप से रहने को सुनिश्चित करने के मानदंड क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) कर्मचारियों के, दिल्ली टेलीफोन्स के कार्यभार ग्रहण करने पर महानगर टेलीफोन निगम लि० के पूल से प्राथमिकता के आधार पर वैकल्पिक आवास आवंटित किया जाता है, बशर्ते कि क्वार्टर उपलब्ध हों और कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कर्मचारी के पास किसी अन्य पूल का नियमित रूप से आवंटित क्वार्टर हो।

(ख) उस पूल के नियंत्रण प्राधिकारी से इस बात की पुष्टि की जाती है कि क्या इस कर्मचारी को पहले के पूल से नियमित आधार पर क्वार्टर आवंटित था।

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लि० द्वारा संपदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय के अनुदेशों का पालन किया जाता है, कर्मचारी को पहले के पूल में क्वार्टर सामान्य प्रतीक्षा सूची के अनुसार, उनकी बारी आने पर आवंटित हुआ होना चाहिये।

Entrusting of Rural Telecom Network to the Private Sector/Multinationals

2496. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government propose to open the rural telecom network to the private sector/multinationals;

(b) if so, the details thereof;

(c) what are the modafities finalised in this regard and the number of villages to be benefitted under this scheme;

(d) what is the number of proposals received from the private sector alongwith the details thereof; and

(e) by when the network is likely to be opened?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The proposal is under consideration. DOT proposes to open the virgin rural areas for private sector participation. Details are being worked out. During Eighth Plan it is proposed to cover all 2,32,054 Panchayat villages and another 1.5 lakh villages for provision of public telephones.

(d) Nil.

(e) During current Five Year Plan.

संचार मंत्रालय में ठेके के आधार पर कराये जाने वाले काम

2497. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय में काम ठेके के आधार पर कराये जा रहे हैं ;

(ख) इन कामों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार ठेकेदारों को दी गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है ;

(घ) किस-किस प्रकार के कामों को ठेके पर कराया जा रहा है ;

(ङ) क्या यह पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है कि ये ठेके अधिकारियों के सम्बन्धियों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा लिये गए हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मामलों की जांच के लिए कोई निर्णय लिया है?